Pariwarik Dastak (Indore) 19 January, 2017

खाद्य सुरक्षा की व्यापक नीति आवश्यकः अध्ययन

इंदौर। अपार सम्भावनाओं से भरे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नयी जान फूंकने के लिये केन्द्र सरकार को एक व्यापक खाद्य सुरक्षा योजना बनाने की जरूरत है। एसोचैम के राष्ट्रीय महासचिव डी. एस. रावत और टारी की निदेशक सुश्री क्षमा कौशिक ने कहा कि इस योजना में अन्तर्राष्ट्रीय परिकल्पनाओं तथा दिशानिर्देशों को शामिल किया जाना चाहिये, ताकि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिये कृषि उत्पादों की आपूर्ति को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा सके।

एसोचैम-टारी के संयुक्त अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है। द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया (एसोचैम) और थॉट आर्बिटरेज रिसर्च इंस्टीट्यूट (टारी) द्वारा किये गये फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री- कंट्रीब्यूटिंग टू मेक इन इंडिया (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग- मेक इन इंडिया में योगदान) विषयक अध्ययन में रेखांकित करते हुए कहा गया है कि अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने, रसद के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि में अत्याधुनिक

तकनीक का इस्तेमाल करने और प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहयोग देकर श्रमिकों की क्षमता बढ़ाने से भारत को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का हब बनाने में खासी मदद मिलेगी। अध्ययन में रेखांकित करते हुए कहा गया है कि बड़े कृषि संसाधन आधार के साथ-साथ श्रमिकों को सस्ता पारिश्रमिक, कच्चे माल की उपलब्धता से नजदीकी वाली जगह, संगठित खुदरा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि, सरकारी नीतियों पर सही अमल, बढ़ता शहरीकरण और बढ़ती हुई प्रतिव्यक्ति आय के कारण पैकेज्ड भोजन को दी जाने वाली तरजीह इत्यादि ऐसे कारक हैं जो भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देते हैं।